Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

बैंकों का एकीकरण एवं उनका आर्थिक प्रभाव

डॉ. कल्पना निरंजन
एसोसिएट प्रॉफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
आर्यकन्या पी.जी. कॉलेज, झाँसी

आज से करीब 52 वर्ष पहले 19 जुलाई 1969 को वित्त मंत्रालय ने एक घोषणा की जिसके अनुसार देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वो निजी बैंक जिनके पास 50 करोड़ रूपये से ज्यादा की पूंजी थी उन्हें राष्ट्रीयकरण करके भारतीय बैंकिंग की मुख्यधारा में ले लिया गया। यह राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री श्रमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। सन् 1980 में एक बार फिर भारतीय बैंकिंग के इतिहास ने करबट ली, 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 200 से पूँजी रखने वाले छह निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद भारत में राष्ट्रीयकरण बैंकों की कुल संख्या 20 हो गई थी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अगला नेसर्गिक कदम था बैंकों का विलय करके एक बड़ी बैंक का निर्माण, सन् 1993 में न्यू ऑफ इंडिया और पीएनबी का विलय हुआ और सरकारी बैंकों की संख्या 19 रह गई। सन् 2019–20 में फिर से बैंकिंग के इतिहास ने नयी करवट ली, 13 बैंकों का आपस में विलय किया गया और अस्तित्व में आये पांच बैंक और सरकारी बैंकों की संख्या 11 रह गयी।

प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसके बाद उनका विलय, इन कदमों की आलोचना भी काफी हुयी। मगर यहाँ पर ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी का वक्तव्य काफी मायना रखता है उन्होंने कहा था ''बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीणों के भाग्य ही बदल जायेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर विकास के समान अवसर उपलब्ध होने से राष्ट्रीय एकता में बहुत मदद होगी।'' ऐसा होने के बाद ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा का penetration तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इस क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। छोटी बैंकों के बड़ी बैंकों में विलय को केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। छोटी बैंकें अक्सर स्थानीय लोगों के दबाव में आकर बट्टा खाता लोन दे बैठती हैं और बाद में ये लोन उन्हें एन पी एन बनने की ओर धकेल देते हैं।

52 वर्ष पहले हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इम्पैक्ट क्या है इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि सन् 1969 के पहले भारत को अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था। आज सार्वजनिक क्षेत्र के

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

बैंकों के द्वारा दिए गए कृषि लॉन के कारण भारत में खाद्यान की कोई कमी नहीं है। कृषि क्षेत्र में यह विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के दम पर संभव हो सका है। बैंकों के केन्द्रिकरण के बाद जब बहुत सारा पैसा योग्य होथों में पहुँचा तो उसे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के उन व्यापारियों को दिया गया जो व्यापार के साथ भारत में पब्लिक एसेट बनाने की मंशा रखते थे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गयी। पहले जो बैंक निजी क्षेत्र के गिने चुने लोगों की सेवा करते थे अब वे ही बैंक प्रति वर्ष लाखों बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार प्रदान करते हैं।

बैंको का निजीकरण

इस वर्ष फरवरी में बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के सभी दरवाजे खोले तो इस कदम की बड़ी आलोचना हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राष्ट्रीयकरण को उलटने का फैसला हुआ तो देश के जमाकर्ता के लिए ये घातक कदम साबित हो सकता है। उनका कहना है कि निजीकरण के बाद ज्यादातर बैंक मुनाफा कमाने की होड़ में लग जायेंगे। अभी उनकी मंशा पब्लिक एसेट बनाने की होती है, मगर निजीकरण के बाद बैंक अपनी मर्जी के मालिक हो जायेगे, इस कदम के दुष्परिणाम स्वरूप ये भी हो सकता है कि जनता का कमाया और बहुत सारा पैसा गलत होथों में चला जाये। या फिर ऐसे हाथों में चला जाये जहाँ उसका गुणात्मक प्रभाव देश की आधारभूत सरंचना की पहुँच के बाहर हो।

वैसे बैंकों के विलय के पीछे अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि यदि देश को अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़, की अर्थव्यवस्था बनना है तो देश में बड़े बैंक्स की नितांत आवश्यकता है। इस वजह से बीते 30 अगस्त को मादी सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की घोषणा कर दी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया जाएगा। अनुमान है कि इस विलय के बाद इनका सम्मिलित कारोबार तकरीबन 17.94 लाख करोड़ रूपये के आसपास पहुँच जायेगा। इस स्थिति कें ये बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कहलायेगा। इसके अलावा यदि केनरा बैंक और सिंड़ीकेट बैंक का विलय होता है तो सम्मिलित कारोबार 15.20 लाख करोड़ रूपये का स्तर छुएगा और ये बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसी तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय 14.59 लाख करोड़ रूपये का सम्मिलित कारोबार करेंगे और ये पांचवा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। कुलमिलाकर विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 की जगह सिर्फ 12 रह जायेगी।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

बहुत सारे लोग निजीकरण और एकीकरण का फर्क नहीं जानते हैं। बैंकों का एकीकरण मतलब कई सारी छोटी बैंक जब एक बड़े बैंक के साथ गोल्डन शेक–हैण्ड करती हैं और एक बड़े बैंक का निर्माण करती हैं। बैंक का निजीकरण मतलब बैंक का मालिकाना हक किसी बड़े वित्तीय संस्थान के पास सीमित समय के लिए चले जाना। इस स्थिति में वे वित्तीय संस्था बैंक के चुनिन्दा एसेट का इस्तेमाल मुनाफा के लिए कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था को Neo-liberalism कहा जाता है, इसके अंतर्गत सरकार एक नियत धनराशि के बदले अपने किसी एसेट को प्राइवेट सेक्टर को निश्चित समय के लिए दे देती है। उस समय अन्तराल में निजी क्षेत्र का प्लयर सरकार द्वारा नियुक्त नियामक की गाइडलाइन तले उस एसेट का व्यासायिक उपयोग कर सकता है एवं मुनाफा भी कमा सकता है। बैंक्स के निजीकरण से करकार को परोक्ष लाभ या सीधा फायदा मिलता है।

बैंकों के एकीकरण से किस तरह फायदा हो सकता है इसका उदाहरण हम स्टेट बैंक के मामले में देख सकते हैं, ये बैंक अब 52.05 लाख करोउ रूपये का कारोबार करता है और वैश्विक स्तर पर यह 50 बड़े बैंकों की श्रेणी में गिना जाता है। इस तरह के बड़े बैंक्स निश्चय ही भारत के अन्राष्ट्रीय व्यापार को एक नए स्तर पर ले जायेंगे, जब इस तरह के बैंक अन्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उत्पादों और समूहों का समर्थन करेंगे तो उन्हें साख कमाने में काफी मदद मिलेगी। भारत यदि विश्व मानचित्र पर अपने ब्रांड्स और सर्विसेज को प्रस्तुत करना चाहता है तो उन्हें SBI जैसे बैंकों को Guarantor के तौर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा बहुत सारे देश भारतीय ब्रांड्स के विपगण में तकनीकी अडचने लगा सकते हैं। मौजूद परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक बैंकों का एकीकरण ही एक आवश्यक विकल्प है, क्योंकि आज बैंकों को मार्किट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारी–भरकम पूंजी की जरूरत है। छोटे बैंक अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं क्योंकि निजी बैंक और अंतराष्ट्रीय बैंक लगातार नयी सेवाओं के साथ ग्राहकों को लुभा रहे हैं। ऑनलाइन सर्विसेज और इ–कॉमर्स के आने के बाद बैंकिंग का स्परूप बदला ही, इस स्थिति में ज्यादातर ग्राहक उन बैंकों को चुनना चाहते हैं जिनके नेटवर्क बड़े हो या फिर जिनकी compatibility अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मजबूत हो। छोटे बैंक अक्सर इन मानदंडों पर खुद को असहाय पाते हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि केंद्र की निगाहों से दूर होने की वजह से छोटे बैंक धोखाधड़ी का शिकार भी हो रहे हैं। इस धोखाधड़ी में बैंक के कर्मचारियों और अफसरों की क्या भूमिका है इसका आंकलन करना भी आवश्यक है। यदि छोटे बैंक एक केंद्रीकृत संस्थान के अधीन उनकी मोनिटरिंग में रहेंगे तो इस स्थिति का बेहतर सामना कर पायेंगे। इस समय बहुत सारे भ्रष्टाचार बड़ी बैंक द्वारा नियुक्त ऑडिटर की निगाह में आयेंगे और इस तरह की घटनाओं में कमी होगी।

Saarth
E-Journal of Research
ISSN NO: 2395-339X

आज जब भारत सरकार गली मोहल्लों और दूरदराज गाँवों में बैंकिंग सेवा पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं, एकीकरण के बाद में अस्तित्व में आये बड़े बैंक इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर ये भी समझना आवश्यक हो जाता है कि पेटीएम जैसे डिजिटल वालेंट के आने के बाद गाँव के लोगों को पैसे के डिजिटल लेनदेन के लिए बड़े आसान आप्शन भी मिलने लगे हैं, इन आप्शन की वजह से छोटी बैंकों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गयी है (अपाध्याय, 2020)

बैंकिग क्षेत्र के एक्सपर्ट मानते हैं कि एकीकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की उपस्थिति बढ़ेगी और ये माइक्रो–अर्थव्यवस्था भी एक्टिव रूप से देश व विदेश की बड़ी बैंक्स और अन्य संस्थानों से जुड़ पाएगी। बैंक्स के एकीकरण के समर्थन में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि छोटे बैंक ना तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर पा रहे हैं और ना ही सस्ती दर ग्राहकों को कर्ज दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उस स्तर के एसेट ही नहीं हैं। विलय के बाद यही बैंक एक नए इलाके अैर ग्राहकों के समूह को अन्तराष्ट्रीय स्तर की सेवाओं से जोड़ देते हैं। प्रबंधन की भाषा में इसे विन–विन फॉर आल का नाम दिया जाता है (मौर्या, 2020)

शाखाओं और कार्यालयों के बेहतर समायोजन के लिये कुछ शाखाओं को बंद या दूसरे शाखा के साथ विलय किया जा सकता है, जिसके कारण आईएफएससी और एमआईसीआर कोड में बदलाव करना होगा। हालाँकि सावधि जमा या कर्ज ब्याज दरों में मियाद पूरी होने तक किसी तरह के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मगर ये सारी दिक्कते शुरूआती दिक्कते भर हैं, इस तरह के विलय या एकीकरण की वजह से छोटी बैंक के ग्राहकों को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें मिलने वाली सेवाओं का स्तर सुधर जाएगा।

एकीकरण की प्रक्रिया

बैंकों के एकीकरण में सबसे बड़ी अड़चन होती है मानव संसाधन एवं प्रौधोगिकी, वेतन व भत्ते, प्रणाली, आदि में एकरूपता का नहीं होना। इस स्थिति में बैंक के कर्मचारी यूनियन को विलय के लिए राजी करना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। इस तरह के प्रयास 2003 से लगातार किये जा रहे थे और वर्षों की मेहनत के बाद ऐसा विनियोजन प्लान बन पाया जिसमें सभी पक्षों को संतुष्ट किया जा सके और निर्बाध रूप से बैंकों का विलय हो जाए।

इस तरह का पहला सटीक एवं सफल प्रयास किया था आरएस गुजराल की अध्यक्षता में बनी समिति ने। इस समितिने सरकार को अपनी रिपोर्ट जनवरी 2012 में दी थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिलाकर 7 बड़े बैंक बनाने का सुझाव दिया गया था।

Saarth
E-Journal of Research

ISSN NO: 2395-339X

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण का रोडमैप बैंक बोर्ड व्यूरो ने तैयार किया था और इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छह समूहों में बांटा गया था। बैंकों के समूहों कानिर्णय मानव संसाधन, ई–गवर्नेस, आंतरिक लेखा–परीक्षा, धोखाधड़ी, सीबीएस (कोर बैंकिंग साल्यूशन) एवं वसूली को आधार बनाकर लिया गया था। हालाँकि सरकारी बैंकों के एकीकरण की दिशा में तेजी मादी सरकार के आने के बाद आई। मोदी सरकार की वन नेशन योजना के लिए भी बैंकों का विलय अत्यंत जरूरी था। बड़े स्तर पर वित्तीय संस्थानों के मिल जाने के बाद छोटी बैंकों के लिए व्यापार में बने रहना ही मुश्किल होता जा रहा था। पहले बैंकों का विलय उसके बाद निजीकरण इस समय दो आवश्यक कदम बन गए हैं जिनके बिना पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना साकार करना संभव नहीं है। बैंकिंग के निजीकरण को एन पी ए से भी जोड़कर देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि निजीकरण के आने के बाद बैंकों के एन पी ए में गिरावट आएगी क्योंकि निजी क्षेत्र के लोग कभी भी परोक्ष रूप से घाटा नहीं उठाना चाहेंगे। हालांकि बैंकों के निजीकरण के बारे में बात करते समय उन लोगों की राय को सामने रखना भी आवश्यक है जिनका मानना है कि इस तरह के निजीकरण की वजह से बैंक पिछड़ जायेगी और फिर से वही युग लौट आएगा जा सवर्गीय इंदिरा गांधी के समय में था।

References

उपाध्याय, अ. आगे जाकर पीछे लौटने की नीति है बैंकों का निजीकरण. ***हस्तक्षेप***

https://www.hastakshep.com/privatization-of-banks-the-policy-of-going-back-and-forth-vijay-shankar-singh/.

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/work-continues-on-privatization-of-two-public-sector-banks/articleshow/91795630.cms.